

विषय वस्तु

- जल शक्ति अभियान चरण -2 का शुभारंभ और केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
- भारत-बांग्लादेश की जल संसाधन सचिव स्तरीय बैठक
- सचिव (डब्ल्यूआर, आरडी और जीआर) का केंद्रीय जल आयोग का दौरा
- सरयू नदी (घाघरा) पर अयोध्या बैराज के लिए आईडब्ल्यूआरडी, उत्तर प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन
- सीएपी परियोजना चरण I की संचालन समिति और तकनीकी उप समिति की बैठक
- निवेश मंजूरी समिति की 15वीं बैठक
- भारत ईयू जल भागीदारी (आईडब्ल्यूपी) के दूसरे चरण के लिए बैठक
- माही बजाज सागर बांध, राजस्थान के डिजाइन बाढ़ अनुमान में उप-जलग्रहण आकार का संवेदनशीलता विश्लेषण
- वृहत, मध्यम और लघु सिंचाई सेंसस और जल निकाय सेंसस - प्रक्रियाओं को एकीकृत करना
- परवन वृहत बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, राजस्थान
- भारत और यूरोपीय संघ के बीच समझौता ज्ञापन के तहत जेडब्ल्यूजी बैठक
- तपोवन विष्णुगढ़ जलविद्युत परियोजना की बहाली के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की टीम (टीओई) का दौरा
- "कंक्रीट टनल लाइनिंग का डिजाइन, पोलावरम सिंचाई परियोजना, केस स्टडी" और "फ्राउड नंबर के इंटेक-पैरामीट्रिक अध्ययन के हाइड्रोलिक डिजाइन" पर प्रस्तुति
- राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर की रिलाइनिंग
- शीट पाइल कॉफ़रडैम पर आयोजित प्रस्तुति: भद्रभूत बैराज परियोजना, गुजरात के डिजाइन, विश्लेषण और निर्माण अभ्यास
- सुवर्णरेखा सिंचाई दक्षता पायलट परियोजना पर वेबिनार
- डिप
- वीसी के माध्यम से ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थायी समिति की 69वीं बैठक
- सरस्वती विरासत परियोजना, हरियाणा
- ट्रेड टॉक: चमोली प्लड : हाऊ वी केन बिल्ड रेजिलिएन्स
- उत्तर प्रदेश में पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और एनआईपी के तहत परियोजनाओं के लिए निगरानी दौरे
- एनवायरोटेक एशिया सम्मेलन 2021 में सिंचाई सुधार/आधुनिकीकरण की दिशा में के.ज.आ. के उपक्रम पर प्रस्तुति
- डेटा कॉर्नर- राष्ट्रीय परियोजना की स्थिति
- आईआईएससी, बेंगलुरु/आईआईटी रुड़की में नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम



एस. के. हालदार
अध्यक्ष

संदेश

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22.03.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व जल दिवस के अवसर पर 'जल शक्ति अभियान : कैच द रेन' अभियान की शुरुआत की। केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री की उपस्थिति में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों की ओर से संबंधित मुख्यमंत्रियों द्वारा एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए। यह नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) की पहली परियोजना है। अपनी स्थापना के बाद से, केंद्रीय जल आयोग एनपीपी की तैयारी, विभिन्न प्लेटफार्मों पर इसके आगे के अनुनय और आवश्यक तकनीकी सहायता आदि प्रदान करने से जुड़ा हुआ है।

केंद्रीय जल आयोग ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया देशों के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय चर्चा में भाग लिया। भारत और बांग्लादेश जल संसाधन के मुद्दों जैसे नदी जल बंटवारे की रूपरेखा, प्रदूषण शमन, नदी संरक्षण, बाढ़ प्रबंधन, बेसिन प्रबंधन आदि के सभी पहलुओं में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। केंद्रीय जल आयोग बांग्लादेश की गंगा-पद्म बैराज परियोजना पर संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन के संचालन के लिए भी सहयोग कर रहा है। केंद्रीय जल आयोग भारत में सिंचाई दक्षता में सुधार के लिए अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को पायलट करने का भी प्रयास कर रहा है और इस संबंध में ओडिशा में सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना के लिए

ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग जारी है। केंद्रीय जल आयोग 2016 में स्थापित भारत ईयू जल भागीदारी (आईडब्ल्यूपी) के लिए भी एक महत्वपूर्ण भागीदार है। आईडब्ल्यूपी का दूसरा चरण 2020 में शुरू किया गया था और यह सितंबर, 2023 तक जारी रहेगा।

केंद्रीय जल आयोग ने अयोध्या, उत्तर प्रदेश में सरयू नदी (घाघरा नदी) पर प्रस्तावित अयोध्या बैराज की डिजाइन कंसल्टेंसी और डीपीआर तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रस्तावित बैराज में घाटों पर पानी के प्रवाह की निरंतर उपलब्धता, मौजूदा कमांडों में सिंचाई सुविधाओं का स्थिरीकरण, शहरी और ग्रामीण पेयजल मांगों को पूरा करना, पर्यटन विकास और नौकायन के अवसरों में वृद्धि जैसे कई लाभों की परिकल्पना की गई है।

इस महीने की शुरुआत में श्री पंकज कुमार, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने केंद्रीय जल आयोग, मुख्यालय का दौरा किया, जो विभाग का कार्यभार संभालने के बाद उनका पहला दौरा था। इस महीने के दौरान, देश भर में केंद्रीय जल आयोग कार्यालयों ने स्वच्छता पखवाड़ा में सक्रिय रूप से भाग लिया और स्वच्छता और पानी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए। इस तरह के आयोजनों की झलक न्यूजलेटर के अगले भाग में दी गई है।

अंत में, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि एजेंसियों के निर्देश के अनुसार कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें। सभी पात्र पाठकों, अधिकारियों/कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और दूसरों को भी इसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

प्रो. ज. क. म. म.



भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान

COVID19 का टीका लगाने के लिए
www.cowin.gov.in या
आरोग्य सेतु एप पर रजिस्टर करें



दवाई भी
कड़ाई भी

अधिक जानकारी के लिए www.mohfw.gov.in पर जाएं

जल शक्ति अभियान चरण -2 का शुभारंभ और केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

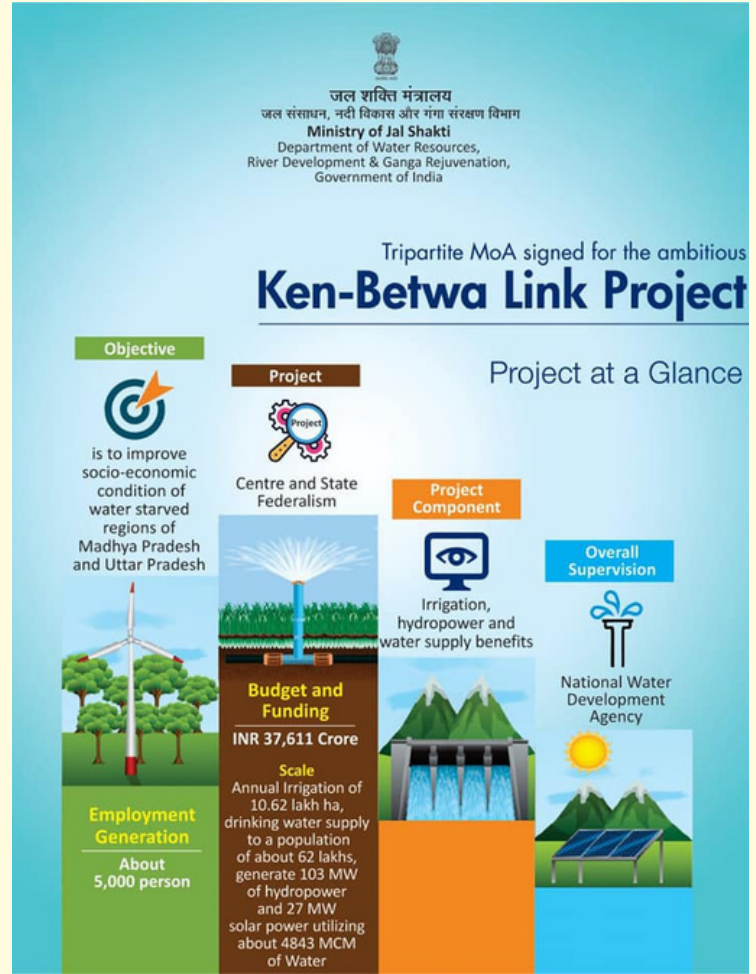


प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने 22.03.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व जल दिवस के अवसर पर 'जल शक्ति अभियान : कैच द रेन' अभियान की शुरुआत की। केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए प्रधान मंत्री की उपस्थिति में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों की ओर से संबंधित मुख्यमंत्रियों द्वारा एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए। यह नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) की पहली परियोजना है। अपनी स्थापना के बाद से, केंद्रीय जल आयोग एनपीपी की तैयारी, विभिन्न प्लेटफार्मों पर इसके आगे के अनुनय और आवश्यक तकनीकी सहायता आदि प्रदान करने से जुड़ा हुआ है।

केन-बेतवा नदी को जोड़ने से बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने और समृद्धि लाने में मदद मिलेगी। इस परियोजना से छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, विदिशा, सागर, दमोह, शिवपुरी, रायसेन और दतिया (मध्य प्रदेश में) और बांदा, महोबा, ललितपुर और झांसी (उत्तर प्रदेश में) जिलों को लाभ होगा। इस परियोजना में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में केन नदी से अधिशेष पानी को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी में स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई है। परियोजना के लिए व्यापक रिपोर्ट

भारत-बांग्लादेश की जल संसाधन सचिव स्तरीय बैठक

संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी) के ढांचे के तहत भारत-बांग्लादेश जल संसाधन सचिव स्तर की बैठक 16.03.2021 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री पंकज कुमार, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने किया और बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री कबीर बिन अनवर, वरिष्ठ सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश सरकार ने किया। दोनों पक्ष नदी के पानी के बंटवारे, प्रदूषण को कम करने, नदी तट संरक्षण, बाढ़ प्रबंधन, बेसिन प्रबंधन आदि के लिए रूपरेखा सहित जल संसाधन के मुद्दों के पूरे क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए। एक संयुक्त तकनीकी कार्य समूह इस मामले में इनपुट प्रदान करेगा। चर्चा सारगर्भित थी और सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित की गई थी। दोनों पक्षों ने पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथियों पर ढाका में जेआरसी ढांचे के तहत जल संसाधन सचिव स्तर की



एनडब्ल्यूडीए द्वारा तैयार की गई थी जिसमें दौधन बांध, लोअर ओर् बांध, बीना कॉम्प्लेक्स एमपीपी, कोठा बैराज, बरियारपुर पिकअप वियर, परीछा वियर व बरवा सागर बांध आदि की मरम्मत/मजबूती का कार्य शामिल है। यह उत्तर प्रदेश को 10.62 लाख हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई, 1,700 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) पानी व लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति प्रदान करेगा और 103 मेगावाट जलविद्युत उत्पन्न करेगा।



बैठक के अगले दौर को निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की।

सचिव (डब्ल्यूआर, आरडी और जीआर) का केंद्रीय जल आयोग का दौरा

श्री पंकज कुमार, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने 01.03.2021 को केंद्रीय जल आयोग, मुख्यालय का दौरा किया। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग का कार्यभार संभालने के बाद केंद्रीय जल आयोग, मुख्यालय की यह उनका पहला दौरा था। अपने दौरे के दौरान, उन्हें केंद्रीय जल आयोग द्वारा की जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। इस संबंध में अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग द्वारा एक संक्षिप्त प्रस्तुति प्रस्तुत की गई। समीक्षा बैठक में आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी / डी एंड आर), केंद्रीय जल आयोग ने भाग लिया।

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने न केवल निर्माण चरण के दौरान बल्कि संसाधनों के बेहतर उपयोग और दक्षता के लिए परियोजनाओं के पूरा होने के बाद भी पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत लागू की जा रही जल संसाधन परियोजनाओं की उचित निगरानी पर जोर दिया। उन्होंने सामुदायिक स्तर पर उचित भागीदारी के लिए भविष्य में छोटी



परियोजनाओं पर अधिक ध्यान देने का सुझाव दिया। इसके अलावा, उन्होंने जल संसाधनों की बेहतर मांग / आपूर्ति प्रबंधन के लिए जल मूल्यांकन अध्ययन की आवृत्ति बढ़ाने और पिछले दशकों में वर्षा और पानी की उपलब्धता के पैटर्न में उच्च जलवायु परिवर्तन को देखते हुए एनडब्ल्यूए के पाठ्यक्रम को बदलने का सुझाव दिया। उन्होंने एनडब्ल्यूए की गतिविधियों और जल गुणवत्ता पहलुओं के लिए केंद्रीय जल आयोग द्वारा की जा रही गतिविधियों के बारे में एक संक्षिप्त स्थिति भी मांगी।

सरयू नदी (घाघरा) पर अयोध्या बैराज के लिए आईडब्ल्यूआरडी, उत्तर प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन

अयोध्या, उत्तर प्रदेश में सरयू नदी (घाघरा नदी) पर प्रस्तावित अयोध्या बैराज की डिजाइन कंसल्टेंसी और डीपीआर तैयार करने के लिए केंद्रीय जल आयोग और सिंचाई और जल संसाधन विभाग, सरकार के बीच 26.03.2021 को 3.40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रस्तावित अयोध्या बैराज उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में सरयू (घाघरा) नदी पर स्थित होगा। अयोध्या बैराज योजना में लगभग 900 से 1000 मीटर लंबे बैराज निर्माण की परिकल्पना की गई है जो यह सुनिश्चित करेगा कि:

- घाटों पर जल प्रवाह की सतत उपलब्धता
- 45,000 हेक्टेयर के मौजूदा कमान क्षेत्र में खरीफ और रबी मौसम में सिंचाई सुविधाओं के स्थिरीकरण का प्रावधान
- भविष्य में अयोध्या शहर को शहरी और ग्रामीण जलापूर्ति की पेयजल मांगों को पूरा करना
- पर्यटन विकास और नौवाहन के अवसरों में वृद्धि



सरयू का अयोध्या में स्थल दृश्य

केंद्रीय जल आयोग, मुख्यालय, नई दिल्ली की डिजाइन इकाई के साथ चर्चा के बाद, केंद्रीय जल आयोग की एक विशेषज्ञ टीम ने बैराज एक्सिस को अंतिम रूप देने और इसकी आवश्यकता सहित बैराज के अन्य मुद्दों को संबोधित करने के लिए आईडब्ल्यूआरडी, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ परियोजना स्थल का 03.03.2021 से 05.03.2021 तक दौरा किया।

सीएपी परियोजना चरण I की संचालन समिति और तकनीकी उप समिति की बैठक

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), दूरसंचार विभाग (डीओटी) और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ टेलीमैटिक्स (सी-डीओटी) के सहयोग से प्रभावित आबादी को विभिन्न प्रकार की आपदाओं के बारे में अलर्ट भेजने के लिए एक कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) विकसित कर रहा है, जिसमें पूर्व चेतावनी दी जाती है। संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) द्वारा जांच के बाद ये अलर्ट विभिन्न मीडिया जैसे एसएमएस, सेल ब्रॉडकास्ट, रेडियो और टीवी प्रसारण के माध्यम से सीधे प्रभावित आबादी को भेजे जाने हैं। यह प्रणाली प्रयोगात्मक रूप से 2020 के दौरान तमिलनाडु के लिए शुरू की गई थी और निकट भविष्य में पूरे भारत में इसका विस्तार किया जा रहा है।

उक्त गतिविधि के लिए संचालन समिति की अध्यक्षता सदस्य (एनडीएमए) करते हैं और अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग इस समिति

के सदस्यों में से एक हैं। पूरे देश में जल्द से जल्द सेवाओं का विस्तार करने के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा की गई गतिविधियों की समीक्षा के लिए संचालन समिति की बैठक 26.03.2021 को आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, सी-डॉट द्वारा यह सूचित किया गया कि केंद्रीय जल आयोग ने गतिविधि के विस्तार के लिए सभी प्रारंभिक आवश्यकताओं को पहले ही पूरा कर लिया है और एनडीएमए ने संकेत दिया है कि केवल लेवल फोरकास्टिंग स्टेशनों के लिए अलर्ट सीएपी प्लेटफॉर्म पर भेजे जाएंगे क्योंकि विभिन्न मीडिया के माध्यम से आम जनता के लिए इसे सीधे भेजा जाता है। तदनुसार, यह सहमति हुई है कि सीएपी प्लेटफॉर्म पर केवल लेवल फोरकास्ट स्टेशन के लिए अलर्ट साझा किए जाएंगे और जब सिस्टम पूरे देश के लिए तैयार होगा और तमिलनाडु के लिए अलर्ट, यदि कोई हो, वैसा ही जारी किया जाएगा जैसा जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है।

निवेश मंजूरी समिति की 15वीं बैठक

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की निवेश मंजूरी समिति की 15वीं बैठक 25.03.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में कर्नाटक, हिमाचल

प्रदेश, राजस्थान और बिहार सरकार तथा इनके अलावा केंद्रीय जल आयोग, जीएफसीसी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समिति द्वारा कुल ग्यारह (11) परियोजनाओं पर विचार किया गया, जिनमें से सात (7) परियोजनाओं को निवेश मंजूरी के लिए अनुशंसित किया गया था। चार (4) परियोजनाओं को स्थगित/अनुशंसित नहीं किया गया। परियोजना का विवरण तालिका में दिया गया है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	श्रेणी	लागत (रु.) करोड़ में और मूल्य स्तर	लाभ	स्थिति	टिप्पणी
1	ऊपरी भद्रा सिंचाई परियोजना	कर्नाटक	प्रमुख	16125.48 (2018-19)	सीसीए -2.25 लाख हेक्टेयर	अनुशंसित	टीएसी की 147वीं बैठक में स्वीकृत
2	सुखा हर मध्यम सिंचाई परियोजना	हिमाचल प्रदेश	मध्यम	153.80 (2015)	सीसीए -2186 हेक्टेयर	आस्थगित	टीएसी की 131वीं बैठक में स्वीकृत
3	परवन बहुउद्देशीय परियोजना	राजस्थान	बहुउद्देशीय	6398.78 (2018)	सीसीए-2.01 लाख हेक्टेयर	अनुशंसित	टीएसी की 135वीं बैठक में स्वीकृत
4	बाली टोला (नजरमीरा) से सबलपुर पछियारी टोला में गंगा नदी के बाएं किनारे पर कटाव रोधी कार्य	बिहार	बाढ़	45.10 (2019)	संरक्षित क्षेत्र 1553 - हेक्टेयर लाभान्वित जनसंख्या- 50000	अनुशंसित नहीं	टीएसी की 145वीं बैठक में स्वीकृत
5	बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना चरण III (बी)	बिहार	बाढ़	913.215 (2018)	लाभान्वित क्षेत्र 130900- हेक्टेयर लाभान्वित जनसंख्या - 50.40 लाख	अनुशंसित	टीएसी की 145वीं बैठक में स्वीकृत
6	परसौरी से महिषा तक 4.60 कि.मी. तक विस्तारित सिकराहडामझरी लो बंड का निर्माण	बिहार	बाढ़	41.92 ((2019	लाभ प्राप्त क्षेत्र 6500 - हेक्टेयर लाभान्वित जनसंख्या- 85000	अनुशंसित	टीएसी की 145वीं बैठक में स्वीकृत
7	बाएं कमला बलान तटबंध पर 7.38 किमी टूटे बांध की मरम्मत का कार्य(गांव-टेरहा), 36.60 किमी(गाम-रखवारी) दायां कमला बलान तटबंध पर 40.60 किमी टूटे बांध की मरम्मत का कार्य(गांव-गोपालखा), किमी 47.30 (गांव-नरुआर), किमी 55.80 पर (गांव-काठीवाड़), किमी 57.50 (गांव-काकोडा), किमी 71.80 (गांव-कुम्हारौल), और किमी 79.60 (गांव- वाथ मंसरा)	बिहार	बाढ़	74.11 (2019)	लाभान्वित क्षेत्र -72300 हेक्टेयर लाभान्वित जनसंख्या-7.5 लाख	अनुशंसित नहीं	टीएसी की 145वीं बैठक में स्वीकृत
8	बाएं भूतही बलान तटबंध का 25.00 किमी से 31.610 किमी (घोघरडीहा से परसा हाट के पास निर्मली रेलवे लाइन तक) का विस्तार	बिहार	बाढ़	48.44 ((2019	लाभ प्राप्त क्षेत्र - 16900 हेक्टेयर लाभान्वित जनसंख्या-3 लाख स्वीकृत	अनुशंसित	टीएसी की 145वीं बैठक में स्वीकृत
9	बक्सर, भोजपुर और पटना जिले में गंगा नदी के बाएं और दाएं किनारे पर अलग-अलग बिंदुओं पर कटाव रोधी/पुनर्स्थापन कार्य	बिहार	बाढ़	67.87 (2019)	लाभान्वित क्षेत्र -76200 हेक्टेयर लाभान्वित जनसंख्या- 13.83 लाख	अनुशंसित नहीं	टीएसी की 145वीं बैठक में स्वीकृत
10	तहसील नाहन, जिला सिरमौर, में मार्कंडेय नदी पर बाढ़ नियंत्रण परियोजना का चैनलीकरण	हिमाचल प्रदेश	बाढ़	105.66 (2019)	लाभकारी क्षेत्र 462 - हेक्टेयर लाभान्वित जनसंख्या- 17406	अनुशंसित	टीएसी की 147वीं बैठक में स्वीकृत
11	सिरमौर जिले में गाम रजबन (हरिजन बस्ती) और नवादा के पास गिरि नदी का चैनलीकरण	हिमाचल प्रदेश	बाढ़	24.77 (2019)	लाभ प्राप्त क्षेत्र- 233.56 हे.	अनुशंसित	चूंकि योजना की लागत 25 करोड़ से कम है, यह तकनीकी रूप से आर्थिक रूप से मूल्यवर्धित और जीएफसीसी द्वारा स्वीकृत है।

बांग्लादेश की गंगा-पद्म बैराज परियोजना (जीबीपी) के संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन के संचालन के लिए भारत-बांग्लादेश संयुक्त तकनीकी समिति के भारतीय पक्ष की पहली बैठक

बांग्लादेश की गंगा-पद्म बैराज परियोजना (जीबीपी) के संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन के संचालन के लिए भारत-बांग्लादेश संयुक्त तकनीकी समिति की पहली बैठक सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ. की अध्यक्षता में 10.03.2021 को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई। बैठक के दौरान, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर द्वारा अग्रेषित और बांग्लादेश सरकार से प्राप्त समिति के संदर्भ की शर्तों (टीओआर) के मसौदे के विभिन्न प्रावधान के बारे में चर्चा की गई और सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे संशोधन के

लिए आवश्यक अपने बहुमूल्य इनपुट/सुझाव प्रदान करें। इसके अलावा, मेसर्स वाप्कोस से अनुरोध किया गया था कि जेटीसी के भारतीय पक्ष के विचार के लिए जल्द से जल्द एक मसौदा आरएफपी तैयार किया जाए। बैठक में के.ज.आ. के अधिकारियों के अलावा डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर, विदेश मंत्रालय, सीडब्ल्यूपीआरएस, आईआईटी रुड़की, सीआईएफआरआई और मेसर्स वाप्कोस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

भारत ईयू जल भागीदारी (आईईडब्ल्यूपी) के दूसरे चरण के लिए बैठक

श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. ने 17.03.2021 को यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल और जीआईजेड के साथ भारत ईयू जल भागीदारी के दूसरे चरण के लिए कॉन्सेप्ट नोट और भारत यूरोपीय संघ जल सहयोग संयुक्त कार्य समूह (JWG) के दूसरी बैठक के अजेंडा को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक बुलाई।

बैठक में आईईडब्ल्यूपी के समग्र उद्देश्य (इंडिया ईयू एमओयू के अनुसार) को कॉन्सेप्ट नोट में रखा गया और आईईडब्ल्यूपी के पहले चरण के 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में किए गए कार्यों पर संक्षेप में चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि चरण-1 के 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को चार विषयगत स्तंभों के तहत देखा जाएगा:

- नदी बेसिन प्रबंधन;
- सिंचाई और कुशल जल उपयोग;
- पर्यावरण प्रवाह मूल्यांकन; तथा
- उपचारित जल का सुरक्षित पुनः उपयोग

माही बजाज सागर बांध, राजस्थान के डिजाइन बाढ़ अनुमान में उप-जलग्रहण आकार का संवेदनशीलता विश्लेषण

सुश्री पायल गोयल, सहायक निदेशक, जल विज्ञान (दक्षिण) निदेशालय ने 01.03.2021 को "डिजाइन बाढ़ अनुमान में उप-जलग्रहण आकार की संवेदनशीलता विश्लेषण" पर एक प्रस्तुति दी।

डिजाइन बाढ़ समीक्षा अध्ययन बांध सुरक्षा समीक्षा का एक अभिन्न अंग है। नदी घाटी परियोजनाओं के लिए डिजाइन बाढ़ का अनुमान आमतौर पर हाइड्रो-मौसम विज्ञान दृष्टिकोण का उपयोग करके लगाया जाता है, जहां डिजाइन स्टार्म और यूनिट हाइड्रोग्राफ दो आवश्यक इनपुट होते हैं। सिद्धांत रूप में, यूनिट हाइड्रोग्राफ का सिद्धांत किसी भी आकार के बेसिन पर लागू होता है। हालांकि, व्यवहार में, यूनिट हाइड्रोग्राफ की व्युत्पत्ति में बुनियादी मान्यताओं को पूरा करने के लिए, स्टार्म का उपयोग करना आवश्यक है, जो समान रूप से बेसिन पर वितरित होते हैं और एक समान दर पर वर्षा का उत्पादन करते हैं। इस तरह के स्टार्म बड़े क्षेत्रों में कम ही आते हैं। जलग्रहण आकार की सीमा आम तौर पर लगभग 5000 वर्ग किमी है, जिसके आगे यूनिट हाइड्रोग्राफ विधि की

वृहत, मध्यम और लघु सिंचाई सेंसस और जल निकाय सेंसस - प्रक्रियाओं को एकीकृत करना

सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. ने एमएमआई सेंसस और जल निकायों की सेंसस के लिए एक आंतरिक समूह का गठन किया है। समूह की पहली आंतरिक बैठक 23.03.2021 को श्री के. वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। प्रारंभ में उन्होंने सदस्यों को देश में सभी परियोजनाओं के डेटाबेस के संकलन के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने यह भी कहा कि देश में यूआईपी, आईपीसी, आईपीयू के लिए डेटा संग्रह और एमएमआई परियोजनाओं के संग्रह के संकलन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए एमएमआई सेंसस और जल निकायों की सेंसस करना आसान होगा।



क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया है और इसे पांच क्रॉस-कटिंग (ऊर्ध्वाधर) स्तंभों में से एक के रूप में रखा गया है।

प्रत्येक विषयगत स्तंभ के लिए नोडल अधिकारियों की पहचान के.ज.आ., सीजीडब्ल्यूबी, एनएमसीजी, डीडीडब्ल्यूएस और डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर से भी की गई थी। भारत ईयू जल भागीदारी का चरण- II 01.11.2020 से 30.09.2023 तक जारी रहेगा।



विश्वसनीयता कम हो जाती है। जलग्रहण आकार की संवेदनशीलता का अनुमान लगाने के लिए, माही बजाज सागर बांध के 6149 वर्ग किमी के जलग्रहण क्षेत्र के डिजाइन बाढ़ पर तीन मामलों पर विचार किया गया- एक एकल जलग्रहण, दो उप-जलग्रहण और पांच उप-जलग्रहण क्षेत्र।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि परियोजना निगरानी संगठन (पीएमओ), के.ज.आ. द्वारा एमएमआई सेंसस और जल निकायों की सेंसस में शामिल किए जाने वाले मापदंडों की एक मसौदा सूची तैयार की जाएगी और समीक्षा और सुझावों के लिए सभी सदस्यों को परिचालित की जाएगी। पहली बैठक में हुई चर्चा के अनुसरण में, पीएमओ द्वारा मापदंडों की एक मसौदा सूची तैयार की गई और सभी सदस्यों को परिचालित की गई।

24.03.2021 को आयोजित दूसरी बैठक के दौरान सदस्यों के सुझावों पर चर्चा की गई। बैठक में हुई चर्चाओं के आधार पर एमएमआई सेंसस और जल निकायों की सेंसस में शामिल किए जाने वाले मापदंडों की एक समेकित मसौदा सूची तैयार की गई है।

परवन वृहत बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, राजस्थान

परवन परियोजना राजस्थान के झालावाड़ जिले में परवन नदी पर स्थित सिंचाई सह पेयजल आपूर्ति परियोजना है। परवन नदी कालीसिंध नदी की एक सहायक नदी है, जो चंबल नदी की मुख्य सहायक नदी है। इस परियोजना में 490 एमसीएम की सकल भंडारण क्षमता के साथ लगभग 38 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसमें से 50 एमसीएम की आपूर्ति राजस्थान के कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों के 820 गांवों को पीने के लिए की जाएगी। परियोजना के लिए के.ज.आ. की वेटिंग कंसल्टेंसी के तहत निर्माण कार्य प्रगति पर है। जीएसआई, जयपुर के मैपिंग रिपोर्ट के अनुसार बांध ब्लॉकों की नींव की विशेषताओं का आकलन करने के लिए के.ज.आ. और डब्ल्यूआरडी, राजस्थान के अधिकारियों की एक टीम द्वारा एक संयुक्त साइट दौरा 04.03.2021 को आयोजित किया गया था। मार्च-2021 के दौरान, परियोजना के विभिन्न घटकों के निम्नलिखित ड्राइंग की जांच की गई और निर्माण के लिए जारी किया गया:



- ब्लॉक संख्या 12 और 13 के अंडर स्लूइस से संबंधित 3 ड्राइंग
- स्पिलवे पियर और क्रेस्ट सुदृढीकरण, डॉवेल व्यवस्था और प्रोफाइल स्टेपिंग विवरण से संबंधित 3 ड्राइंग
- 4 ब्लॉक नं. 5 से 8 के लिए स्टिलिंग बेसिन 1 से 4 में कंक्रीटिंग से संबंधित 4 ड्राइंग

भारत और यूरोपीय संघ के बीच समझौता ज्ञापन के तहत जेडब्ल्यूजी बैठक पर हस्ताक्षर

संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक दो ऑनलाइन सत्रों पहली 24.03.2021 को और दूसरी 31.03.2021 को, में हुई। बैठक की अध्यक्षता अपर सचिव, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर ने की। बैठक में डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर, के.ज.आ., केंद्रीय भूजल बोर्ड, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग, यूरोपीय संघ प्रतिनिधिमंडल और जीआईजेड जर्मनी, हंगरी और नीदरलैंड के यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ आईडब्ल्यूपी पर अपने संबंधित समझौता ज्ञापन/इरादा समझौतों की अभिव्यक्ति के आधार पर भाग लिया। पुर्तगाल ने वर्तमान यूरोपीय संघ के अध्यक्ष पद की भूमिका में भाग लिया। बैठक के दौरान लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

- आईडब्ल्यूपी परियोजना चरण -1 के सभी 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को नदी बेसिन प्रबंधन, सिंचाई और कुशल जल उपयोग, पर्यावरण प्रवाह मूल्यांकन और उपचारित पानी के

सुरक्षित पुनः उपयोग पर चार विषयगत स्तंभों के तहत आईडब्ल्यूपी परियोजना चरण -2 में लिया जाएगा।

- एजेंडे के तहत अनुसंधान और नवाचार पर बिंदु, यह सहमति हुई कि यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बीच त्रिपक्षीय अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।
- 5वें भारत-यूरोपीय संघ जल मंच के एजेंडा बिंदु के तहत, विषयों की एक शॉर्टलिस्ट (IEWP विषयगत क्षेत्रों / गतिविधियों और अनुसंधान और नवाचार परियोजनाओं के विषयों को ध्यान में रखते हुए बड़ी सूची में से 1-2 विषयों का चयन करना, जैसे शहरी जल योजना, गैर-बिंदु-स्रोत जल प्रदूषण, वर्षा जल संचयन, विभिन्न क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता) आने वाले हफ्तों में तकनीकी स्तर पर प्रारंभिक चरणों के रूप में विकसित किया जाएगा।
- वर्ष 2022 के अंत या 2023 की शुरुआत में अगली JWG बैठक बुलाने पर भी सहमति हुई। यदि आवश्यक हो तो इसे पहले भी किया जा सकता है।

तपोवन विष्णुगढ़ जलविद्युत परियोजना की बहाली के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की टीम (टीओई) का दौरा

विशेषज्ञों की एक टीम (टीओई) ने हाल ही में क्षतिग्रस्त विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना (520 मेगावाट), उत्तराखंड का 15.03.2021 से 19.03.2021 तक दौरा किया। टीम में श्री एस.के. कम्बोज (निदेशक, गेट्स), श्री एन.एस. शेखावत (निदेशक, एचसीडी), श्री मनोज मीणा (निदेशक, बीसीडी) और श्री विवेक जौहरी (उप निदेशक, बीसीडी) और अन्य संबंधित संगठनों (सीईए, जीएसआई और सीएसएमआरएस) के विशेषज्ञ सम्मिलित थे। एचईपी की बहाली के लिए एक व्यापक चरण-वार कार्य योजना तैयार करने के लिए मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड के अनुरोध पर टीओई का गठन किया गया है। 07.02.2021 को हुये एक हिमस्खलन से उत्पन्न फ्लैश फ्लड जिसमें बड़ी मात्रा में गाद और विशाल शिलाखंड मिला हुआ था से परियोजना गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी।



रन-ऑफ-रिवर परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ के पास धौली गंगा नदी पर एनटीपीसी द्वारा विकसित की जा रही है।

"कंक्रीट टनल लाइनिंग का डिजाइन, पोलावरम सिंचाई परियोजना, केस स्टडी" और "फ्राउड नंबर के इंटेक-पैरामीट्रिक अध्ययन के हाइड्रोलिक डिजाइन" पर प्रस्तुति

पोलावरम सिंचाई परियोजना, आंध्र प्रदेश एक राष्ट्रीय परियोजना है, जिसके लिए के.ज.आ. के डिजाइन (एनडब्ल्यू एंड एस) संगठन द्वारा हेडवर्क के लिए डिजाइन परामर्श प्रदान किया जा रहा है। परियोजना के तहत सिंचाई सुरंग एक मुक्त प्रवाह, डी-आकार, 18.1 मीटर व्यास और 1200 मिमी मोटी एम 30 पीसीसी अस्तर के साथ प्रदान की गई है। सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) के नेतृत्व में विशेषज्ञ दल ने परियोजना स्थल के अपने दौरे के दौरान बताया कि 1200 मिमी कंक्रीट लाइनिंग की मोटाई सामान्य डिजाइन अभ्यास के अनुसार नहीं थी और अधिक प्रतीत होती थी और इसलिए, सिफारिश की ताकि के.ज.आ. से इसकी जांच कराई जा सके। तदनुसार, इस अतिरिक्त मुद्दे को डिजाइन (एनडब्ल्यू एंड एस) यूनिट को संदर्भित किया गया था। एचसीडी (एनडब्ल्यू एंड एस) निदेशालय ने इसकी जांच की और उन पर टिप्पणियों को परियोजना प्राधिकरण को भेजा गया। कंक्रीट अस्तर को "कंक्रीट अस्तर के संरचनात्मक डिजाइन" के लिए आईएस कोड 4880-IV के प्रावधान का उपयोग करके डिजाइन किया गया था। यह देखा गया कि आईएस 4880-IV के प्रावधान वृत्ताकार सुरंग के लिए हैं और गैर-गोलाकार या डी-आकार की सुरंग का सटीक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। साथ ही, IS-4880-IV के कई प्रावधान पुराने पाए गए।

उपरोक्त को संबोधित करने के लिए, STAAD सॉफ्टवेयर में नॉन-सर्कुलर डी-शेप कंक्रीट टनल लाइनिंग का संरचनात्मक विश्लेषण किया गया था। विभिन्न मोटाई और भार संयोजनों के लिए विकृतियों और परिणामी प्रतिबलों के पैटर्न का अध्ययन किया गया

उपयुक्त मोटाई और विभिन्न विश्लेषणों के परिणाम संतोषजनक पाए गए। अंतिम को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

24.03.2021 को दी गई प्रस्तुति में, आईएस 4880-IV में कमियों को अद्यतन करने और विभिन्न प्रकार की सुरंगों को कवर करने के लिए इसे और अधिक प्रयोज्य बनाने पर जोर दिया गया था और कंक्रीट टनल लाइनिंग के डिजाइन को STAAD सॉफ्टवेयर में किया गया था और उसके परिणाम पर चर्चा की गई। सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ. ने व्यक्त किया कि मौजूदा कोडल प्रावधानों की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

फ्राउड नंबर के संबंध में इंटेक के हाइड्रोलिक डिजाइन पर भी चर्चा की गई। फ्राउड नंबर का पैरामीट्रिक अध्ययन विभिन्न साहित्य और विभिन्न परियोजनाओं के डेटा का उपयोग करते हुए किया गया था। यह सुझाव दिया गया था कि "हाइड्रोपावर इंटेक्स-हाइड्रोलिक डिजाइन के लिए मानदंड" के लिए IS-9761 कोड के अनुसार $Fr = 0.33$ के अनुशंसित मूल्य के खिलाफ, 0.5 तक के उच्च मूल्यों पर विचार किया जा सकता है क्योंकि कई परियोजनाएं $Fr > 0.33$ के साथ भी संतोषजनक प्रदर्शन कर रही हैं। भौतिक मॉडल अध्ययनों के साथ इसे मान्य करने का सुझाव दिया गया था। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि ऐसा करने से लागत और परियोजनाओं के प्रदर्शन में सुधार होगा।

उपरोक्त प्रस्तुति श्री दर्पण तलवार, निदेशक और सुश्री मनु दुबे, डीडी, एचसीडी (एनडब्ल्यू एंड एस) निदेशालय, के.ज.आ. द्वारा दी गयी।

राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर की रिलाइनिंग

सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में विशेषज्ञ परियोजना समीक्षा समिति की दूसरी बैठक 03.03.2021 को आयोजित की गई थी, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 05.03.2021 और 08.03.2021 को जारी रखा गया था ताकि राजस्थान फीडर आरडी 179000 फीट से 496000 फीट और सरहिंद फीडर आरडी 119700 फीट से 447927 फीट के रिलाइनिंग के संबंध में कार्यों की स्थिति की समीक्षा की जा सके। बैठक के दौरान राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि ने राजस्थान फीडर के प्रस्तावित बंद/कार्य निष्पादन कार्यक्रम के दौरान पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नहर बंद करने की अवधि को कम करने और राजस्थान को पीने के पानी की रिलीज का पुनर्निर्धारण करने का अनुरोध किया। हालांकि, मुख्य अभियंता, नहर, पंजाब सरकार ने बताया कि कुछ क्षेत्र और संविदात्मक मुद्दों के कारण राजस्थान फीडर (आरएफ) में प्रस्तावित नहर बंद करने की अवधि 70 दिनों से घटाकर 45 दिन करना मुश्किल है। वह राजस्थान को इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी और/या वित्तीय प्रभाव की क्षतिपूर्ति से मुक्त करने के आश्वासन पर इस विषय पर विचार करने के लिए सहमत हुए।

समिति के अध्यक्ष ने राजस्थान से पंजाब के उपरोक्त अनुरोध के संबंध में उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने आगे राजस्थान को उभरते परिदृश्य का संज्ञान लेने और उसके परिणाम



के आधार पर उचित निर्णय लेने के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की तकनीकी समिति की बैठक (टीसीएम) जैसे उपयुक्त मंच से संपर्क करने की सलाह दी।

राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि मामले को बीबीएमबी के टीसीएम में उठाने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और बंद करने की अवधि के लिए औपचारिक अनुरोध जो अब प्रस्तावित है, सरकार को भेजा जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने उल्लेख किया कि बंद की अवधि में कमी के कारण कानूनी/वित्तीय प्रभाव के क्षति से पंजाब को मुक्त करने के लिए मामला राजस्थान राज्य में उचित स्तर पर उठाया जाएगा।

शीट पाइल कॉफ़रडैम पर आयोजित प्रस्तुति: भदभूत बैराज परियोजना, गुजरात के डिजाइन, विश्लेषण और निर्माण अभ्यास

सीएमडीडी (एन एंड डब्ल्यू) निदेशालय द्वारा 08.03.2021 को शीट पाइल कॉफ़र डैम - डिजाइन, विश्लेषण और निर्माण प्रथाओं पर एक प्रस्तुति दी गई थी, जिसमें भदभूत बैराज परियोजना में एक कॉफ़रडैम के चल रहे निर्माण का केस स्टडी था। यह परियोजना नर्मदा नदी पर, नदी के मुहाने से 25 किमी ऊपर की ओर, जहां यह खंभात की खाड़ी में बहती है स्थित है।

यह परियोजना बड़ी कल्पसार परियोजना का हिस्सा है, जिसमें भरूच और भावनगर जिलों के बीच खंभात की खाड़ी में 30 किलोमीटर के बांध का निर्माण शामिल है। कल्पसार परियोजना का लक्ष्य गुजरात के 25% औसत वार्षिक सतही जल संसाधनों को संग्रहित करना है। यह जलाशय लगभग 8,000 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) सतही जल का भंडारण करेगा और समुद्र में दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी के जलाशयों में से एक होगा। इससे जलाशय में नर्मदा, महिसागर और साबरमती नदियों के अतिरिक्त पानी का दोहन होगा और लवणता का प्रवेश रुक जाएगा। के.ज.आ. परियोजना के लिए डिजाइन समीक्षा सलाहकार है। वर्तमान में कॉफ़रडैम का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

मुख्य बैराज के निर्माण के लिए नदी का डायवर्जन जरूरी है। डायवर्जन कार्यों के लिए सैंड फिलिंग प्रकार के डबल शीट पाइल कॉफ़र डैम प्रस्तावित किया गया है। दो चादरों के ढेर के बीच स्पष्ट

जलाशय निगरानी

के.ज.आ. देश के 130 जलाशयों की लाइव स्टोरेज स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक जलाशय बुलेटिन जारी करता है। उपरोक्त में से 44 जलाशयों में 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ जल विद्युत लाभ है। इन 130 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 174.233 बीसीएम है जो देश में सृजित 257.812 बीसीएम की सजीव भंडारण क्षमता का लगभग 67.58% है।

25.03.2021 के बुलेटिन के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध लाइव स्टोरेज 76.372 बीसीएम था जो इन जलाशयों की लाइव स्टोरेज क्षमता का लगभग 44% है। हालांकि, पिछले साल इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध लाइव स्टोरेज 89.162

सुवर्णरेखा सिंचाई दक्षता पायलट परियोजना पर वेबिनार

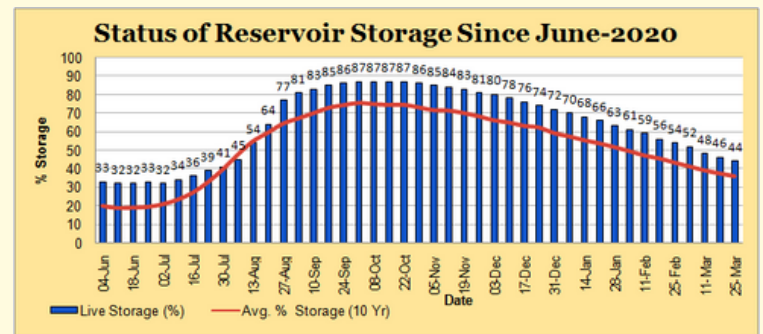
दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में सिंचाई दक्षता गतिविधियों से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई अनुभव को प्रदर्शित करने और सुवर्णरेखा सिंचाई पायलट परियोजना के लिए किए जाने वाले स्कोपिंग अध्ययन पर आगे चर्चा करने के लिए 10.03.2021 को सुवर्णरेखा सिंचाई दक्षता पायलट परियोजना पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था।

श्री पी. दोर्जे ग्याम्बा, मुख्य अभियंता (पोमियो), के.ज.आ. ने ऑस्ट्रेलियाई पक्ष और भारतीय पक्ष के सभी अधिकारियों का स्वागत किया और सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी जिसमें बांध की स्थिति और पहचाने गए अध्ययन क्षेत्र - किचकेश्वरी पानीपंचायत कमांड को दर्शाया गया था।



दूरी 10.0 मीटर रखी गई है। शीट पाइल का शीर्ष स्तर 9.00 मीटर प्रस्तावित है। शीर्ष स्तर +3.00 मीटर के साथ कॉफ़रडैम बर्म के वर्किंग साइड में, शीर्ष पर 7 मीटर चौड़ा और 1 1:2 ढलान वाला प्रस्तावित है। डिजाइन के उद्देश्य के लिए नदी तल स्तर 3.00 मीटर और एचएफएल 7.50 मीटर माना गया है।

मुख्य बैराज का निर्माण दो चरणों में किया जाएगा। चरण -1 में, कॉफ़रडैम का निर्माण बाएं और दाएं किनारे से 400 मीटर तक किया जाएगा और साथ ही बैंक के प्रत्येक किनारे के अंदर साइट की स्थिति के अनुसार आवश्यक लंबाई होगी। फेज-1 में बैराज का निर्माण पूरा होने के बाद फेज-1 में बने कॉफ़रडैम को हटाया जाएगा। चरण-2 में मुख्य बैराज की शेष लंबाई के लिए नदी के मध्य हिस्से में कॉफ़रडैम का निर्माण किया जाएगा।



बीसीएम था और पिछले दस वर्षों के लाइव स्टोरेज का औसत 62.748 बीसीएम था। इस प्रकार, 130 जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के लाइव संग्रहण का 86% और दस वर्ष के औसत संग्रहण का 122% है।

ऑस्ट्रेलियन वाटर पार्टनरशिप (AWP) के भागीदारों ने तीन अलग-अलग दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया, कंबोडिया और वियतनाम में सिंचाई दक्षता परियोजनाओं के लिए स्कोपिंग अध्ययन के तीन मॉडल प्रस्तुत किए।

मुख्य अभियंता (पीओएमआईओ), के.ज.आ. ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना के तहत पहचाने गए कमांड क्षेत्र के बारे में विभिन्न डेटा/सूचना ऑस्ट्रेलियाई पक्ष को अवगत करा दी गई है, इसलिए ऑस्ट्रेलियाई पक्ष द्वारा अब भौतिक-वित्तीय पहलुओं सहित एक प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है और भविष्य की कार्रवाई के संबंध में संयुक्त चर्चा के लिए के.ज.आ. के साथ साझा किया जा सकता है।

ड्रिप

डीआरआईपी चरण - II और III की विभिन्न खरीद संबंधी प्रक्रियाओं पर चर्चा के लिए कार्यशाला

डीआरआईपी चरण- II और चरण- III की विभिन्न खरीद संबंधी प्रक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए 05.03.2021 को एक कार्यशाला वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित की गई। राज्य के अधिकारियों को नई योजना के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान पालन किए जाने वाले खरीद नियमों और विनियमों के बारे में जागरूक किया गया। सीखे गए सबक और चल रहे डीआरआईपी के अनुभव भी प्रतिभागियों के साथ साझा किए गए। सीपीएमयू और विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया और उसके बाद प्रश्नों को हल करने के लिए एक सत्र आयोजित किया। विश्व बैंक और सीपीएमयू के प्रतिनिधियों सहित

अंतिम विश्व बैंक समीक्षा मिशन

अंतिम विश्व बैंक समीक्षा मिशन 10-16 मार्च 2021 के दौरान हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था। मूल डीआरआईपी के परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज (पीएडी) के साथ-साथ अतिरिक्त वित्त पोषण के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति और परिणाम ढांचे की प्रगति पर विचार-विमर्श किया गया था। मिशन में केरल डबल्यूआरडी, केएसईबी, डीवीसी(10.03.2021), टीएएनजीईडीसीओ, तमिलनाडु डबल्यूआरडी, यूजेवीएनएल (11.03.2021), ओडिशा डबल्यूआरडी, मध्य प्रदेश डबल्यूआरडी, कर्नाटक डबल्यूआरडी (12.03.2021), 8 शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने (15.03.2021) शारीरिक

केरल डबल्यूआरडी और कर्नाटक डबल्यूआरडी के बांधों के लिए प्रकाशित ईएपी के कार्यान्वयन के लिए हितधारक परामर्श बैठकें

कार्यान्वयन आवश्यकता के एक भाग के रूप में केरल डबल्यूआरडी के सात बांधों और कर्नाटक डबल्यूआरडी के एक बांध के लिए प्रकाशित आपातकालीन कार्य योजनाओं (ईएपी) के प्रसार के लिए हितधारक परामर्श बैठकें (एससीएम) क्रमशः 09.03.2021 और 26.03.2021 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित की गईं। यह कार्यक्रम सभी हितधारकों को संबंधित जोखिमों को संप्रेषित करने के लिए जोखिम शमन रणनीति का एक हिस्सा है। इन बैठकों में के.ज.आ., एनडीएमए, एसडीएमए, आईएमडी, एनआरएससी, जीएसआई, ऑल इंडिया रेडियो, जिला प्राधिकरण और बांध के नीचे के गांवों के अधिकारियों ने भाग लिया। डीआरआईपी के तहत, कुल 197

जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक के संबंध में देश में ग्लेशियर प्रबंधन पर विस्तृत पृष्ठभूमि नोट को अंतिम रूप देने के लिए अध्यक्ष द्वारा बैठक

दिनांक 08.04.2021 को जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक के संबंध में देश में ग्लेशियर प्रबंधन पर विस्तृत पृष्ठभूमि नोट को अंतिम रूप देने के लिए अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता में 30.03.2021 को एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में के.ज.आ. मुख्यालय के के.ज.आ. अधिकारियों ने भाग लिया। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस),

वीसी के माध्यम से ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थायी समिति की 69वीं बैठक

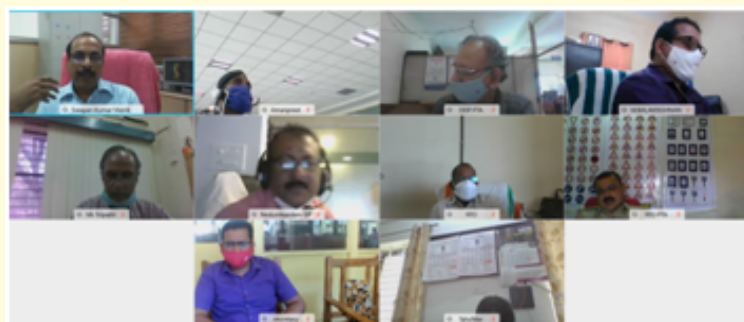
ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थायी समिति की 69वीं बैठक 02.03.2021 को अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। सदस्य (आरएम), के.ज.आ.



18 राज्यों के लगभग 250 अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया।



रूप से भाग लिया। इसके बाद 16.03.2021 को सभी कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ एक वर्चुअल रैप-अप बैठक हुई।



ईएपी प्रकाशित किए गए हैं और 102 हितधारक परामर्श बैठकें आयोजित की गई हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच) के प्रतिनिधि ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया था। उक्त बैठक के दौरान, देश में ग्लेशियर प्रबंधन के संबंध में सभी प्रतिभागियों के बीच एक विस्तृत चर्चा हुई और सभी प्रतिभागियों से संसदीय स्थायी समिति को भेजे जाने वाले पृष्ठभूमि नोट को अंतिम रूप देने के लिए विस्तृत इनपुट/टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया गया।

ने इस समिति के सदस्य के रूप में बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड से जुड़े विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी मामलों पर चर्चा की गई।

सरस्वती विरासत परियोजना, हरियाणा

निदेशक, सीएसएमआरएस, श्री एसएल गुप्ता की अध्यक्षता में सरस्वती परियोजना क्षेत्र में के.ज.आ., सीएसएमआरएस, जीएसआई और हरियाणा सिंचाई और जल संसाधन विभाग (एचआईडब्ल्यूआरडी) के अधिकारियों का संयुक्त निरीक्षण सोम-सरस्वती बैराज, सरस्वती जलाशय और इंटरकनेक्टिंग पाइपलाइन के भू-तकनीकी जांच आवश्यकताओं की समीक्षा के लिए 05.03.2021 को किया गया। श्री मनोज कुमार मीणा, निदेशक बीसीडी (एन एंड डब्ल्यू) और श्री विवेक जौहरी, उप निदेशक बीसीडी (एन एंड डब्ल्यू) ने के.ज.आ. से संयुक्त दौरे में भाग लिया।

टीम ने रामपुर-गैंडा पुल के 477 मीटर यू/एस पर स्थित पुराने बैराज अक्ष का निरीक्षण किया, जहां जीएसआई के अधिकारियों ने हिमालय के विवर्तनिक, जमीनी गति/तनाव, जल-भूवैज्ञानिक और रॉक मास पहलुओं पर विशेष जोर देते हुए विभिन्न हानिकारक भूवैज्ञानिक विशेषताओं पर विचार-विमर्श किया फ्रंटल थ्रस्ट (HFT) ने पुराने बैराज अक्ष के 175m d/s को उजागर किया। क्षेत्र में प्रमुख पुरा-भूकंपीय घटनाओं के साथ ऐसी विशेषताओं के जुड़ाव पर भी प्रकाश डाला गया। उपरोक्त विशेषताओं के कारण और ऐसी अवांछित भूवैज्ञानिक विशेषताओं को कम करने के लिए, GSI द्वारा पुराने बैराज अक्ष से $\pm 250\text{m}$ u/s पर सुझाए गए वैकल्पिक अक्ष पर भी टीम द्वारा विचार-विमर्श किया गया। टीम, जीएसआई के विचार-विमर्श, लेआउट योजना के संबंध में बाधाओं, HIWRD अधिकारी द्वारा विचार-विमर्श किए गए वैधानिक मंजूरी और किसी भी बैंक में आधार की उपलब्धता को देखते हुए एक नए वैकल्पिक बैराज अक्ष के चयन के लिए सहमत हुई। टीम के सदस्यों ने जीएसआई द्वारा सुझाए गए आधार क्षेत्र के भूवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए 70 मीटर की गहराई वाले 5 ड्रिल होल और के.ज.आ. द्वारा सुझाए गए बैराज



और संबंधित डिजाइनिंग संरचनाओं के लिए आवश्यक विभिन्न परीक्षण/जांच करने के लिए 25 मी गहराई वाले अतिरिक्त 6 ड्रिल के लिए सहमति व्यक्त की।

सरस्वती जलाशय क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान, सीएसएमआरएस के अधिकारी ने खुदाई की गहराई तक 500 मीटर x 500 मीटर के ग्रिड पैटर्न पर मिट्टी की जांच के लिए परीक्षण का सुझाव दिया। टीम ने जलाशय क्षेत्र में किसी भी पुरा चैनल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए भी अध्ययन करने का भी सुझाव दिया।

विभिन्न स्थानों पर टीम द्वारा प्रस्तावित पाइपलाइन संरेखण का भी दौरा किया गया जहां टीम ने एचआईडब्ल्यूआरडी को उपयुक्त स्थानों पर बुर्जी के रूप में फील्ड ग्राउंड मार्किंग बनाने और विभिन्न स्थानों पर मिट्टी की जांच करने की सलाह दी। पाइपलाइन का संशोधित संरेखण एचआईडब्ल्यूआरडी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

ट्रेड टॉक: चमोली फ्लड : हाऊ वी कैन बिल्ड रेजिलिएन्स

श्री एन.एन. राय, निदेशक, जल विज्ञान (दक्षिण) निदेशालय ने 22.03.2021 को "चमोली फ्लड : हाऊ वी कैन बिल्ड रेजिलिएन्स" पर एक ट्रेड टॉक वेबिनार दिया। हाल ही में चमोली घटना और जीएलओएफ (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड) जैसे हिमनदों के उभार से नुकसान को कम करने की आवश्यकता है। हिमालयी क्षेत्र में, प्रमुख नदियाँ ग्लेशियरों से निकलती हैं जहाँ मीठे पानी के संसाधनों का बड़ा हिस्सा बर्फ और स्नो में बंद है। पिछले कुछ दशकों में, ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऊपरी हिमालयी क्षेत्र में अनिश्चित हिमनद झीलों का निर्माण हुआ है। बर्फ और हिमपात की तीव्र दर के कारण, संभवतः ग्लोबल वार्मिंग के कारण, इन झीलों में जल संचय हिमालय में बढ़ रहा है। ग्लेशियर के किनारे पर स्थित झीलें मुख्य रूप से पार्श्व या अंत मोराइन द्वारा बांधी जाती हैं, जहां टूटने की उच्च प्रवृत्ति होती है। ऐसी झीलें खतरनाक हो सकती हैं क्योंकि उनमें बड़ी मात्रा में पानी होता है। टूटना और ऐसी झीलों से पानी का तात्कालिक निर्वहन अचानक बाढ़ का कारण बन सकता है जिससे नीचे की ओर भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है।

जीएलओएफ बहुत उच्च परिमाण के हो सकते हैं। उनका प्रभाव और क्षरण क्षमता इसके हाइड्रोग्राफ के क्षीणन पैटर्न पर निर्भर



करेगी, जिसका अनुमान हाइड्रोडायनामिक रूटिंग के साथ मिलकर बांध तोड़ सिमुलेशन द्वारा लगाया जा सकता है। यह इस तरह के नुकसान को कम करने के लिए बुनियादी ढांचे की निगरानी और योजना बनाने के लिए उपयुक्त उपायों की योजना बनाने और डिजाइन करने में सहायक हो सकता है।

यह वेबिनार सीपीआर-सीडब्ल्यूसी डायलॉग फोरम द्वारा आयोजित किया गया था और इसे निम्नलिखित लिंक से एक्सेस किया जा सकता है:

<https://www.facebook.com/CentreforPolicyResearch/videos/437963490768225/>

उत्तर प्रदेश में पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और एनआईपी के तहत परियोजनाओं के लिए निगरानी दौरे

मध्य गंगा नहर (एमजीसी) परियोजना चरण- II

श्री जी.एल. बंसल, निदेशक और श्री मयंक सुहिरिद, उप निदेशक, के.ज.आ., आगरा ने 15-18 मार्च, 2021 के दौरान एमजीसी परियोजना चरण- II की दूसरी निगरानी यात्रा की। सिंचाई और जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी यात्रा के दौरान उनके साथ थे। मुख्य नहर, शाखाओं और वितरण प्रणाली में ग्राम सड़क पुल (VRB), अनंतिम सड़क पुल (PRB), साइफन एक्वाडक्ट आदि के रूप में पक्के कार्यों पर भूमि अधिग्रहण, मिट्टी और निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना की कुल प्रगति लगभग 68% है। परियोजना को पूरा करने की लक्ष्य तिथि मार्च, 2022 है। मध्य गंगा नहर (एमजीसी) परियोजना चरण- II में मानसून के दौरान गंगा नदी के 1943 एमसीएम अधिशेष पानी को यूपी में अमरोहा, संभल और मुरादाबाद जिलों में खरीफ सिंचाई के लिए बिजनौर में मौजूदा चौधरी चरण सिंह बैराज के लेफ्ट बैंक रेगुलेटर

अर्जुन सहायक परियोजना

उक्त अधिकारियों ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ 23-25 मार्च, 2021 के दौरान अर्जुन सहायक परियोजना का भी दौरा किया। अर्जुन फीडर, कबराई फीडर में मिट्टी का काम, कबराई बांध और मुख्य नहर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और पक्के कार्यों जैसे वीआरबी, पीआरबी, साइफन एक्वाडक्ट आदि का निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना की समग्र प्रगति लगभग 96 प्रतिशत है। परियोजना को पूरा करने की लक्ष्य तिथि जून, 2021 है।

अर्जुन सहायक परियोजना में मौजूदा लहचुरा बांध से फीडर चैनलों के माध्यम से अर्जुन, चंद्रवाल और कबराई बांधों को भरने के लिए बरसात के मौसम में धसान नदी के 279 एमसीएम अधिशेष पानी के उपयोग की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना 44381 हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई प्रदान करेगी जिसमें से खरीफ क्षेत्र 18963 हेक्टेयर और रबी 25418 हेक्टेयर है। इसके

कचनोदा बांध निर्माण परियोजना, उ.प्र.

उपरोक्त अधिकारियों ने "कचनोदा बांध निर्माण परियोजना, उत्तर प्रदेश" का भी दौरा किया, जो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत चिह्नित एक परियोजना है। 22-23 मार्च, 2021 के दौरान सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, ललितपुर, उत्तर प्रदेश के संबंधित अधिकारियों के साथ सामना किए जा रहे विभिन्न मुद्दों / बाधाओं पर चर्चा की गई और के.ज.आ., मुख्यालय को दौरे की रिपोर्ट जमा कर दी गई है।

इन्वायरोटेक एशिया सम्मेलन 2021 में सिंचाई सुधार/आधुनिकीकरण की दिशा में के.ज.आ. के उपक्रम पर प्रस्तुति

दिनांक 07.03.2021 को जल और अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पर इन्वायरोटेक एशिया ऑनलाइन प्रदर्शनी में श्री संजय कुमार सिंह, निदेशक, के.ज.आ. द्वारा "सिंचाई प्रदर्शन / आधुनिकीकरण में सुधार की दिशा में के.ज.आ. की उपक्रम" पर एक प्रस्तुति दी गई। जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, पीएमकेएसवाई, स्वच्छ भारत मिशन जैसे वर्तमान उद्यमों के साथ-साथ के.ज.आ. की उपक्रमों जैसे सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए समर्थन, प्रदर्शन मूल्यांकन और सिंचाई परियोजनाओं के बेंचमार्किंग पर चर्चा की गई।



के माध्यम से उपयोग करने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना में 2.55 लाख हेक्टेयर का जीसीए और 2.25 लाख हेक्टेयर का सीसीए है। अंतिम सिंचाई क्षमता 146532 हेक्टेयर है जिसमें से धान और अन्य खरीफ फसलों के तहत प्रस्तावित क्षेत्र क्रमशः 78902 हेक्टेयर और 67630 हेक्टेयर हैं।



अलावा, अर्जुन, चंद्रवाल और कबराई बांधों की मौजूदा कमानों में 15104 हेक्टेयर क्षेत्र को बहाल किया जाएगा। परियोजना के पूरा होने पर यूपी के मोहाबा, हमीरपुर और बांदा जिले लाभान्वित होंगे। दोनों परियोजनाएं पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत शामिल हैं।



डेटा कॉर्नर- राष्ट्रीय परियोजना की स्थिति

क्र. सं.	राष्ट्रीय परियोजना के नाम/राज्य	लाभ : 1) सिंचाई (हेक्टेयर) 2) पावर (मेगा वाट) 3) भंडारण (एमसीएम)	(स्थिति 25.03.2021 तक)
1	घोसीखुर्द सिंचाई परियोजना/ महाराष्ट्र	1) 2.50 लाख 2) 26.5 3) 1147.14 (सकल)	जारी
2	सरयू नहर परियोजना/ उत्तर प्रदेश	14.04 (राष्ट्रीय परियोजना (एनपी) घटक: 4.73 2) शून्य 3) बैराज	जारी
3	पोलावरम सिंचाई परियोजना/ आंध्र प्रदेश	1. 4.36 लाख 2. 960 3. 5511 (सकल)	जारी
4	शाहपुरकंडी बांध परियोजना/ पंजाब	1) 0.37 लाख 2) 206 3) 120.71 (सकल)	जारी
5	तीस्ता बैराज परियोजना/ पश्चिम बंगाल	1) 9.23 लाख (राष्ट्रीय परियोजना 5.27) 2) 1000 3) Barrage	1.97 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित की गई। हालांकि, भूमि अधिग्रहण के मुद्दों के कारण परियोजना 2014-15 से रुकी हुई है।
6	लखवार बहुदेशीय परियोजना/ उत्तराखंड	1) 0.3378 लाख 2) 300 3) 587.84 (सकल)	जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत
7	रेणुका जी बांध परियोजना/ हिमाचल प्रदेश	1) पेय जल 2) 40 3) 498.33 (सजीव)	जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत
8	किशाऊ बहुदेशीय परियोजना/ हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड	1) 0.97 लाख 2) 660 3) 1824 (सकल)	संशोधित डीपीआर तैयार की जा रही है
9	उझ बहुदेशीय परियोजना/ जम्मू एवम कश्मीर	1) 0.77 लाख 2) 196 3) 925 (सकल)	जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत
10	केन बेतवा लिंक परियोजना/ मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश	1) 9.04 लाख (सी सी ए) 2) 78 3) 3495 सजीव	द्वितीय चरण का मूल्यांकन जारी
11	कुलसी बांध परियोजना/ असम	1) 0.0395 लाख (जी आई ए) 2) 55 3) 525.64 (सकल)	मूल्यांकन चरण
12	नोआ दिहिंग बांध परियोजना/ अरुणाचल प्रदेश	1) 0.036 लाख (सी सी ए) 2) 72 3) 322.00 (सकल)	मूल्यांकन हो चुका है
13	जिसपा परियोजना/ हिमाचल प्रदेश व्यास परियोजना/ पंजाब	1) 1.74 लाख (अप्रत्यक्ष) 2) 800 3) 616.74 (सकल)	मूल्यांकन चरण
14	ऊपरी सियांग परियोजना/ अरुणाचल प्रदेश	1) 0.50 लाख (है.) 2) 300 3) 912.78 (सजीव)	डीपीआर चरण
15	दूसरी रवि व्यास लिंक परियोजना/ पंजाब	सीमाओं के पार बहने वाले पानी का दोहन (गैर-मानसून अवधि में लगभग 0.58 एमएएफ)	पीएफआर चरण
16	ऊपरी सियांग परियोजना/ अरुणाचल प्रदेश	1) (अप्रत्यक्ष) 2) 9750 3) 1776.21 (सकल) 4 बांध नियंत्रण	पीएफआर चरण

प्रशासनिक समाचार

- श्री एस.के. हालदार, अध्यक्ष, के.ज.आ. को दिनांक 01.01.2021 (पीछे) से 6 महीने की अवधि के लिए अध्यक्ष, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

- श्री आदित्य शर्मा, मुख्य अभियंता, नर्मदा बेसिन संगठन, के.ज.आ., भोपाल को दिनांक 04.02.2021 से 6 माह की अवधि के लिए कार्यकारी सदस्य, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।



योजनाओं/घटकों की वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ में)

क्र सं	योजना/घटक का नाम	राजस्व (2020-21)	व्यय (मार्च 2021 तक)	व्यय (प्रतिशत में)
1.	डेलवपमेंट ऑफ़ वाटर रिसोर्सेज इनफार्मेशन (डब्ल्यू आर आई एस)	130.00	128.535	98.9%
2.	इन्वेस्टीगेशन ऑफ़ वाटर डेवलपमेंट स्कीम (आई डब्ल्यू आर डी)	9.00	8.299	92.2%
3.	फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम (एफ एम बी ए पी)	10.576	9.3574	91.7%
4.	इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (आई डी) स्कीम	5.75	5.7357	99.75%
5.	नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट (एन एच पी)	8.886	8.903	101.53%
6.	डैम रेहबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (ड्रिप)	21.80	21.45	98.40%

प्रशिक्षण

क्र सं	कार्यक्रम का नाम	तिथियां और अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	श्रेणी
I	प्रशिक्षण कार्यक्रम			
क)	स्कूली शिक्षकों के लिए भारत के जल संसाधन क्षेत्र पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम - बैच 1	01 से 03 मार्च 2021	156	जन जागरण
ख)	सीडब्ल्यूसी के सहायक अनुसंधान अधिकारियों के लिए अनिवार्य कैंडर प्रशिक्षण कार्यक्रम	08 से 19 मार्च 2021	27	कैंडर
ग)	"पायथन प्रोग्रामिंग और जावा स्क्रिप्ट" पर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	08 से 26 मार्च 2021	20	उद्देश्य उन्मुख
घ)	सिंचाई परियोजनाओं के लिए नहर संरक्षण की बुनियादी अवधारणाओं पर प्रशिक्षण-सह-वेबिनार	11, 12 तथा 15 मार्च 2021	29	उद्देश्य उन्मुख
II	कार्यशाला			
च)	पाइप सिंचाई नेटवर्क की योजना, डिजाइन और कार्यान्वयन पक्ष पर कार्यशाला	05.03.2021	20	कार्यशाला

आईआईएससी, बेंगलुरु/आईआईटी रुड़की में नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

बांध इंजीनियरिंग में नियमित स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम की शुरुआत और बांध सुरक्षा में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना डीआरआईपी चरण- II और चरण- III के तहत महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। तीन शैक्षणिक संस्थान जैसे आईआईटी रुड़की, आईआईएससी बेंगलुरु और आईआईटी मद्रास ने इस पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम के लिए आईआईएससी बेंगलुरु और आईआईटी रुड़की में प्रवेश प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र 2021 के लिए चल रही है। केंद्रीय और राज्य डीआरआईपी कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारी इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। को शुरू करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। इस

जल क्षेत्र समाचार

- ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने में तेजी ला रहा चीन, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर असर (हरिभूमि, 09.03.2021)
- मोदी ने भारत—बांग्लादेश को जोड़ने वाले 'मैत्री सेतु' का किया उद्घाटन (राष्ट्रीय सहारा, 10.03.2021)
- नमामि गंगे की आधी रकम भी खर्च नहीं हुई (हिन्दुस्तान, 10.03.2021)
- देश के सात करोड़ ग्रामीण घरों तक पहुंचा नल से जल (दैनिक जागरण, 10.03.2021)
- 63 साल बाद फेनी नदी पर बंधी मैत्री की डोर (दैनिक जागरण, 10.03.2021)
- स्पाइसजेट को साबरमती रिवर फ्रंट से 'स्टैच्यू आफ यूनिटी' तक उड़ान भरने की अनुमति (राष्ट्रीय सहारा, 11.03.2021)
- देश के सभी 4378 शहरों में 2.86 करोड़ घर पानी कनेक्शन से जुड़ेंगे (दैनिक भास्कर, 12.03.2021)

- चीनी संसद से ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध निर्माण की योजना पारित (पंजाब केसरी, 12.03.2021)
- भारत—पाक के सिंधु आयुक्तों की बैठक 23—24 मार्च को (जनसत्ता, 15.03.2021)
- केन—बेतवा विवाद : उप्र को 750 एमसीएम पानी देने पर सहमति (दैनिक जागरण, 15.03.2021)
- देशभर में शुरू होगा जलशक्ति अभियान का दूसरा चरण (राष्ट्रीय सहारा, 17.03.2021)
- विश्व जल दिवस विशेष — दुनिया में 78 करोड़ से ज्यादा लोग शुद्ध जल से वंचित (राजस्थान पत्रिका, 21.03.2021)
- मनरेगा का पैसा वर्षा जल संचयन में लगाएं : मोदी (जनसत्ता, 23.03.2021)
- जल जीवन मिशन में देश के शीर्ष सात राज्यों में गुजरात नंबर एक (राजस्थान पत्रिका, 31.03.2021)

इतिहास - कंगसाबती जलाशय परियोजना

पश्चिम बंगाल के लिए वरदान

वर्ष 1959 में, पश्चिम बंगाल के घनी आबादी वाले राज्य में खाद्य उत्पादन के संबंध में आत्मनिर्भरता की दिशा में बांकुरा से लगभग 35 मील की दूरी पर गोराबारी में 126 फीट ऊंचे कंगसाबती बांध पर काम का उद्घाटन एक और विशिष्ट कदम था। यह परियोजना सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है, कंगसाबती नदी के बाढ़ के पानी को रोकती है, जिससे मिदनापुर कस्बे से दूर मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत मिलती है। वर्ष 1784 में पूरा हुआ मिदनापुर के पास एक एनीकट, कंगसाबती जलाशय परियोजना से पहले कंगसाबती में मौजूद एकमात्र सिंचाई संरचना थी।

नदी

कंगसाबती नदी छोटानागपुर की पहाड़ियों में समुद्र तल से 2,103 फीट ऊपर निकलती है और दक्षिण-पूर्व दिशा में बहती है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों के माध्यम से एक ही दिशा में जारी, नदी लगभग 229 मील के कुल मार्ग के बाद नंदीग्राम के पूर्व में हुगली में प्रवेश करती है। इसके दाहिने किनारे पर कंगसाबती की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां भैरब बांकी, ताराफेनी और कलियाघई। इसके बाएं किनारे पर एकमात्र महत्वपूर्ण सहायक नदी कुमारी है जो अंबिकानगर के पास मिलती है।

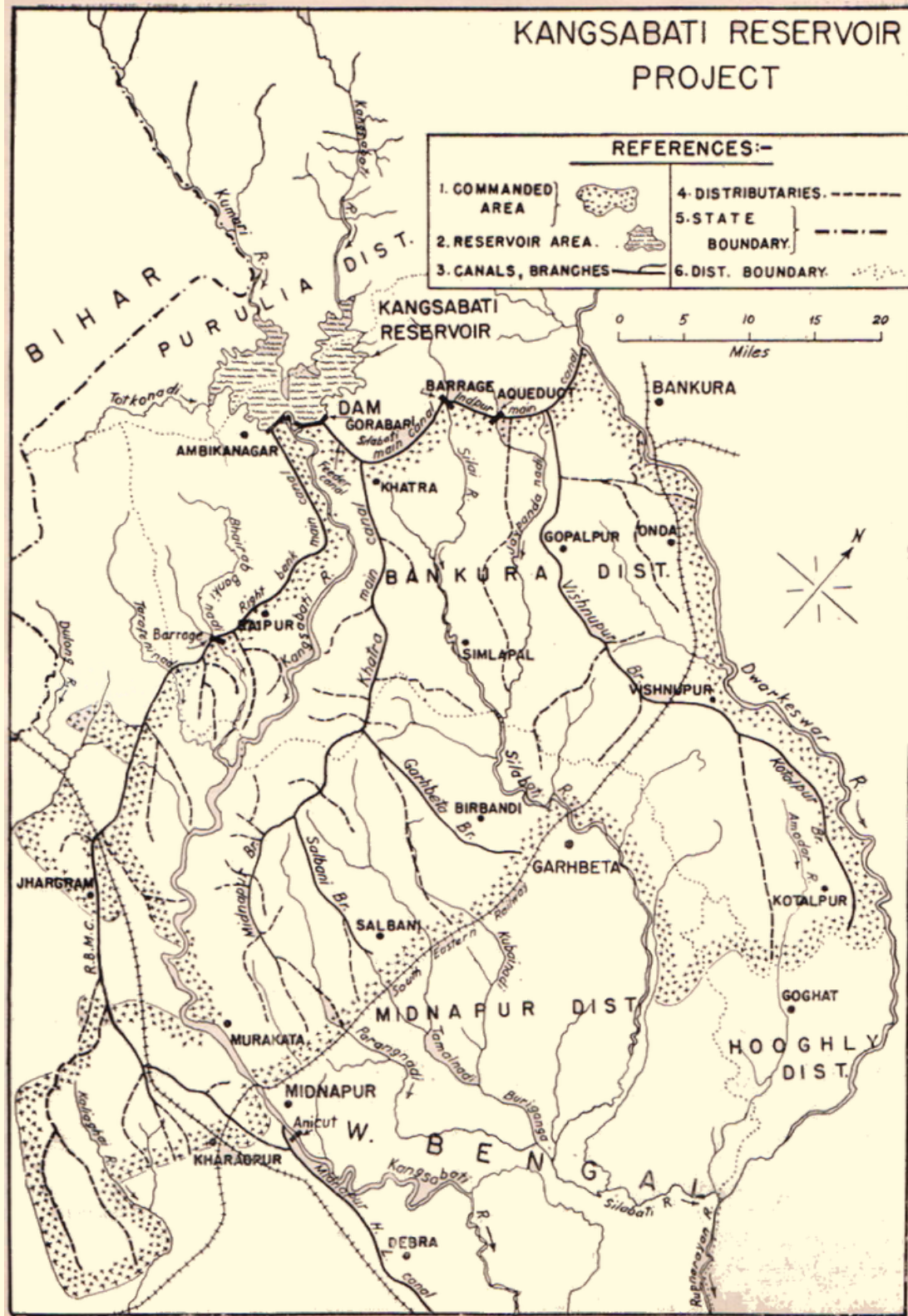
मूल प्रस्ताव

मूल रूप से प्रस्तावित परियोजना में बांकुरा जिले में खतरा के पास एक बांध का निर्माण और बांध से सीधे दोनों किनारों पर नहरें और सिलाबती और भैरब बांकी नदियों पर दो

पिकअप बैराज शामिल हैं। इस परियोजना पर 25.14 करोड़ रुपये खर्च होने का और आठ लाख एकड़ खरीफ और डेढ़ लाख एकड़ रबी फसलों की सिंचाई का अनुमान लगाया गया था।

संशोधित प्रस्ताव

बांध स्थल के स्थान की समीक्षा करनी पड़ी क्योंकि इससे सम्पूर्ण बांध के पूरा होने तक कोई सिंचाई नहीं की जा सकती थी। कोई लाभ प्राप्त होने से पहले इस पर लगभग 18 करोड़ रु व्यय की आवश्यकता पड़ती। इससे पहले तत्कालीन बिहार राज्य में स्थित कंगसाबती जलग्रहण क्षेत्र को पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव था। बंगाल के इंजीनियरों ने इसका लाभ उठाया और



बांध स्थल को ऊपर करने की संभावना की जांच की ताकि बांकुरा जिले के पश्चिमी भाग में कुछ उच्च-स्तरीय भूमि को सिंचाई के तहत लाया जा सके। अंत में उन्होंने अंबिकानगर से लगभग तीन-चौथाई मील ऊपर उस स्थान का चयन किया जहां कुमारी नदी कंगसाबती में मिलती है।

सिंचाई

कंगसाबती परियोजना के कमांड क्षेत्र के भीतर, टैंक, कुओं और कई छोटी सिंचाई योजनाओं के रूप में सिंचाई सुविधाएं पहले से मौजूद हैं। हालांकि, ये लाभ प्रस्तावित क्षेत्र का केवल एक छोटा सा अंश है। इस योजना में आठ लाख एकड़ की खरीफ सिंचाई और

डेढ़ लाख एकड़ की रबी सिंचाई और विकट अवधि के दौरान मिदनापुर नहरों की जरूरतों को पूरा करने की परिकल्पना की गई है। कंगसाबती नहर प्रणाली में 10 रेगुलेटर, 77 नहरें शामिल हैं जो देश में तीव्र फाल्स के पारगमन के लिए हैं और क्रॉसिंग के लिए 131 पुल हैं।

लेफ्ट बैंक कैनाल सिस्टम

बाएं किनारे की नहर प्रणाली से लगभग 80 प्रतिशत कमांड क्षेत्र की सिंचाई होती है। 7,880 क्यूसेक के बहाव के साथ हेड-रेगुलेटर से निकलते हुए, बाएं किनारे की नहर शुरू में फीडर नहर के रूप में और बाद में सिलाबती मुख्य नहर के रूप में तब तक चलती है जब तक कि यह सिलाबती नदी से नहीं मिलती। तत्पश्चात, एक जलसेतु पर जयपांडा नदी को पार करते हुए आखिरी छोर तक (द्वारकेश्वर नदी के पास) यह इंदपुर मुख्य नहर के रूप में बहती है।

राइट बैंक कैनाल सिस्टम

2840 क्यूसेक के प्रवाह के साथ मुख्य बांध के प्रमुख भाग से निकलते हुए दाहिने किनारे की मुख्य नहर भैरव बांकी नदी को पार करती है जहां एक समपार के रूप में काम करने के लिए एक पिक-अप बांध प्रदान किया गया था। छह मील नीचे (डाउनस्ट्रीम) यह ताराफेनी को पार करती है जहां एक जलसेतु प्रदान किया गया

मूल-कंगसबाती परियोजना सुविधाएं एक दृष्टि में		
स्थान	पश्चिम बंगाल के बाकुरा जिले के अबिकानगर में, कुमारी के कंगसाबती के संगम के लगभग 2.4 किमी अपस्ट्रीम पर	
कैचमेंट	3561 वर्ग किमी	
बांध :		
प्रकार	मृदा, रोल्ड फ़िल प्रकार	
ऊँचाई (अधिकतम गहरी नीव से)	कंगसाबती पर	40 मी
	कुमारी पर	41.2 मी
लम्बाई	कंगसाबती पर	5.2 किमी
	कुमारी पर	4.8 किमी
	कनेक्टिंग डैम-	0.4 किमी
	कुल -	10.4 किमी
स्पिलवे	रेडियल गेट युक्त 09 मीटर चौड़ी और 10 मीटर ऊँची 11 बे	
जलाशय :		
जल फैलाव	117 वर्ग किमी	
क्षमता	1135 मिलियन घन मी	
फ़ुल ड्रिस्टांज	5663 क्यूसेक	
नहर प्रणाली :		
मुख्य नहर और वितरण की लंबाई	3862 किमी	
लाभ :		
सिंचाई	3.24 लाख हे.	
लागत	रु. 25.5 करोड़	

है। दाहिने किनारे की मुख्य नहर, खड़गपुर के पास इसके आखिरी छोर तक, कंगसाबती नदी के लगभग समानांतर, कई वितरिकाओं के साथ बहती है।

स्रोत: भगीरथ और सरकारी वेबसाइट

Gallery



दिनांक 26.03.2021 को के.ज.आ. मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा एक स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया



नर्मदा बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग में स्वच्छता पखवाड़ा 16 से 31 मार्च 2021 मनाया गया जिसमें दिनांक 26.03.2021 को इस कार्यालय के अंतर्गत विभिन्न स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाया गया



16.03.2021 से 31.03.2021 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया, के.ज.आ. मुख्यालय नई दिल्ली में श्रमदान के माध्यम से स्वच्छता गतिविधियां



श्री गोवर्धन प्रसाद, निदेशक, जल विज्ञान (उत्तर) निदेशालय ने 23-24 मार्च, 2021 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित स्थायी सिंधु आयोग की 116 वीं बैठक में आयुक्त (सिंधु), जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण के सलाहकार के रूप में भाग लिया

विश्व जल दिवस



पानी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रति वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर अध्यक्ष, के.ज.आ. द्वारा अन्य अधिकारियों के साथ के.ज.आ. मुख्यालय, नई दिल्ली में शपथ ली गई

भारत का अमृत महोत्सव



केजीबीओ, के.ज.आ., हैदराबाद द्वारा 23 मार्च, 2021 को शहीद दिवस समारोह

फील्ड गतिविधि

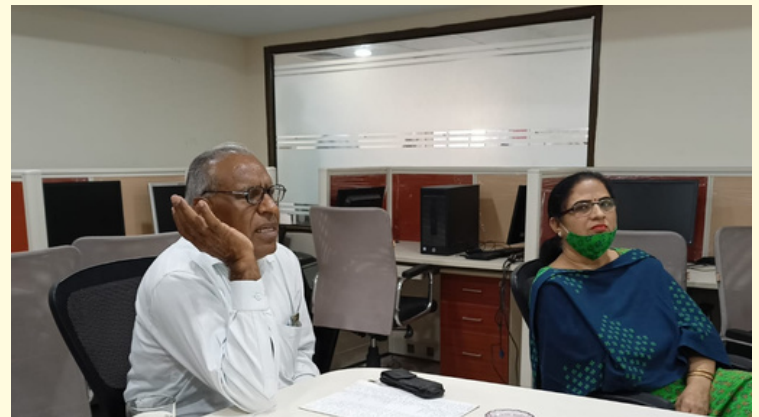


श्री कयूम मोहम्मद, निदेशक एवं श्री. अश्वनी कुमार वर्मा, उप निदेशक ने 03.03.2021 को राजस्थान के गराडा बांध के निर्माण स्थल का दौरा किया



दिनांक 22.03.2021 को विश्व जल दिवस मनाते हुए माही एवं तापी बेसिन संगठन, के.ज.आ., गांधीनगर में "जल और स्वच्छता" से संबंधित मुद्दों पर एक विचार मंच का आयोजन किया गया

हिंदी कार्यशाला



के.ज.आ. (मुख्यालय) में दिनांक 11.03.2021 को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित हिंदी कार्यशाला में आमंत्रित वक्ता श्री प्रेम सिंह, संयुक्त निदेशक (सेवानिवृत्त) ने 'मानक वर्तनी तथा पारिभाषिक शब्दावली' विषय पर प्रभावशाली जानकारी प्रदान की



निदेशक (प्रबोधन) और डीडी (प्रबोधन), के.ज.आ., बेंगलुरु ने दिनांक 30.03.2021 से 31.03.2021 के दौरान राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत सॉथी लिफ्ट सिंचाई योजना का दौरा किया।



केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध
कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता (ईएमओ) - सदस्य
- श्री योगेश पैथकर, मुख्य अभियंता (पीएमओ) - सदस्य
- श्री दीपक कुमार, निदेशक (नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री एस.के. राजन, निदेशक (टीसी) - सदस्य

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

- श्री भूपिन्द्र सिंह, निदेशक (डब्ल्यूपीएंडपी-सी) - सदस्य
- श्री के.वी. प्रसाद, निदेशक (जल प्रणाली अभि.) - सदस्य
- श्री अर्जुन कुमार मधोक, उप निदेशक (ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक (डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री शिव सुन्दर सिंह, उप निदेशक (ज.प्र.अभि.) - सदस्य सचिव

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in

